

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
शहरी विकास निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक-21 फरवरी, 2017

विषय:- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (JnNURM) के उपघटक UIDSSMT के अन्तर्गत स्वीकृत ऋषिकेश हेरिटेज योजना की प्रथम किस्त की अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 955 / IV(2)- श0वि0-2016-03(JnNURM)13, दिनांक 09.06.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से भारत सरकार द्वारा JnNURM के उपघटक UIDSSMT के अन्तर्गत स्वीकृत ऋषिकेश हेरिटेज योजना (लागत ₹1765.90 लाख) के क्रम में प्रथम किस्त की धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित) कुल ₹882.80 लाख के सापेक्ष ₹283.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि JnNURM के उपघटक UIDSSMT के अन्तर्गत स्वीकृत "ऋषिकेश हेरिटेज योजना" हेतु प्रथम किस्त की धनराशि ₹882.80 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹882.80 लाख - ₹283.00 लाख = ₹599.80 लाख (₹ पाँच करोड़ निम्नानवे लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आपके द्वारा आहरित कर कार्यदायी संस्था परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, ऋषिकेश को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ii) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यों हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य मद से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बचत से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (iv) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।
- (v) स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी guidelines/Toolkit एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 09.06.2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग एवं उक्त के सापेक्ष निर्माण कार्य दिनांक 31-03-2017 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूपों पर शासन को उपलब्ध कराए जायेंगे।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-

आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना-04-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण (यू0आई0डी0एस0एम0टी0)- 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नाम ₹461.85 लाख, अनुदान सं0-30, लेखाशीर्षक-2217- शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना-04-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण (यू0आई0डी0एस0एम0टी0)- 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नाम ₹113.96 लाख एवं अनुदान सं0-31, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना- 09-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण (यू0आई0डी0एस0एम0टी0)-20- सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नाम ₹23.99 लाख डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेंट आई जी-s 1702130132, s. 1702300133 एवं s. 1702310134 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्बाल)  
सचिव।

संख्या-187 (1)/IV(2)-श0वि0-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. मेलाधिकारी, अर्द्धकुम्भ-2016, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से समन्वय/पर्यवेक्षण करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य अभियन्ता (परियोजना), गढ़वाल, सिंचाई विभाग, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-1 एवं 2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)  
उप सचिव।